THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभांश में वृद्धि

4772. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभांश की राशि में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 और 1994-95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया और उक्त वर्षों के दौरान इन उपक्रमों द्वारा लाभांश के रूप में कितनी-कितनी राशि अर्जित की गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले इन संस्थानों में अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस अतिरिक्त पूंजी निवेश की राशि कितनी थी और मार्च, 1995 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले इन संस्थानों में कुल कितना पूंजी निवेश हुआ था; और

(ङ) इन उपक्रमों द्वारा लाभांश के रूप में कुल कितनी राशि अर्जित की गई तथा यह लाभांश कुल परियोजना लागत का कितने प्रतिशत था?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घोषित किए गए लाभांश में निरन्तर वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान केवल जिस अवधि तक सूचना उपलब्ध है, लाभ अर्जित किया है उनकी संख्या क्रमशः 133, 131, और 120 है। इन उपक्रमों द्वारा उसी अवधि के दौरान घोषित किया गया लाभांश क्रमशः 687.22 करोड़ रु०, 791.58 करोड़ रुपए और 1014.47 करोड़ रुपए है।

(ग) से (ङ) 31.3.1992, 31.3.1993 और 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार उद्यमवार निवेश की गई राशि और घोषित किए गए लाभांश का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993-94 के खण्ड-III में दिया गया है जिसे 22.3.1995 को सभा पटल पर रख दिया गया था।

Foreign investment proposals pending for clearance

4773. SHRI VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total number of applications of foreign investment which are pending for clearance;

(b) the details thereof state-wise; and

(c) the reasons for the delay in clearing the proposals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) Receipt and consideration of applications for foreign investment is a continuing process. The RBI accords automatic approval for foreign equity investment upto 51% within specified priority sectors and parameters. Such approvals are normally available within two weeks of filing the application. All other proposals which do not conform to the parameters for automatic approvals are considered, on merits, by the Government. Approvals for such cases are normally available

within 4.6 weeks of filing the application. Statewise data on foreign investment approved from 01.01.93 to 31.03.95 is given in the enclosed statement *(see* below). Statewise details of pending proposals arc not centrally maintained.

Statement

Foreign Direct Investment approved (State-wise) for the period January 1993 to March 1995

State	Jan '93—Mar '95	
	Number	Investment (Rs. Million)
Maharashtra	367	54971.68
Others	425	49265.13
West Bengal	77	34499.42
Delhi	197	26789.58
Gujarat	104	18451.60
Tamil Nadu	203	17093.80
Andhra Pradesh	129	11238.23
Madhya Pradesh	42	9133.82
Orissa	18	8152.83
Karnataka	145	5927.72
Punjab	28	5012.80
Rajasthan	62	3627.71
Haryana	115	3394.48
Uttar Pradesh	79	2706.19
Pondicherry	17	1147.33
Goa	19	822.05
Chandigarh	10	723.62
Bihar	8	721.19
Dadra & Nagar Haveli	8	402.76
Kerala	21	354.34
Himachal Pradesh	10	139.65
Arunachal Pradesh	2	110.60
Damar &. Diu	6	54.78
Andaman & Nicobar	5	9.84
Assam	3	9.24
Tripura	1	6.80
TOTAL:	2101	254767.19

विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु नियमों को सरल बनाना

4774 श्री अजीत जोगी:
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु राज्य सरकारों से नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से ही विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं सहित औद्योगिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए राज्य सरकारों से संपर्क बनाएं रखना एक सतत्